

दिल्ली को बाल भिक्षावृत्ति मुक्त बनाने की तैयारी सीएम रेखा गुप्ता ने कहा- विशेष अभियान चलाएंगे

13 जिलों में चलेगा अभियान, बच्चों को सुरक्षित माहौल देने के साथ परिवारों की काउंसलिंग और पुनर्वास पर रहेगा जोर

एजेंसी। नई दिल्ली

दिल्ली सरकार राजधानी को बाल भिक्षावृत्ति से मुक्त करने के लिए व्यापक अभियान शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सभी 13 जिलों में चलाए जाने वाले इस अभियान का उद्देश्य सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर भीख मांगने वाले बच्चों की पहचान कर उन्हें सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है।

सरकार बच्चों को केवल भिक्षावृत्ति से हटाने के बजाय उनके परिवारों की काउंसलिंग, शिक्षा और पुनर्वास पर भी ध्यान देगी। इसके लिए बच्चों और उनके परिवारों को सुरक्षित और टिकाऊ विकल्प उपलब्ध कराने की योजना बनाई जा रही है। सरकार



का मानना है कि बाल भिक्षावृत्ति केवल कानून-व्यवस्था का विषय नहीं है, बल्कि इसके पीछे गरीबी, परिवार की आर्थिक स्थिति, शिक्षा से दूरी और कई सामाजिक कारण भी जुड़े हो सकते हैं। इसलिए प्रस्तावित अभियान में संबंधित विभागों और एजेंसियों के बीच समन्वय पर जोर रहेगा। बच्चों की पहचान के

बाद उनकी जरूरत के अनुसार उन्हें संरक्षण, परामर्श, शिक्षा और पुनर्वास सेवाओं से जोड़ा जाएगा। परिवारों की भी होगी काउंसलिंग: अभियान का एक अहम हिस्सा बच्चों के परिवारों से संपर्क करना होगा। सरकार यह समझने का प्रयास करेगी कि बच्चे किन परिस्थितियों में भीख मांगने

के लिए मजबूर हैं। परिवारों की काउंसलिंग के जरिए उन्हें बच्चों को भिक्षावृत्ति में भेजने से रोकने और उपलब्ध सरकारी सहायता तथा कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने की कोशिश होगी। दिल्ली के समाज कल्याण विभाग के जिम्मे भिक्षावृत्ति की रोकथाम, उपचार और पुनर्वास से जुड़े कार्य पहले से हैं। विभाग दिल्ली में भिक्षावृत्ति रोकने से संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत काम करता है और जरूरतमंद लोगों के लिए संस्थागत तथा गैर-संस्थागत सेवाएं उपलब्ध कराता है।

केंद्र की योजना से भी जोड़ने की तैयारी: बाल भिक्षावृत्ति के खिलाफ दिल्ली की पहल को केंद्र की 'स्माइल' योजना से भी जोड़ा जा सकता है। इस योजना के तहत

भिक्षावृत्ति में शामिल लोगों के व्यापक पुनर्वास के लिए चिकित्सा सुविधा, काउंसलिंग, शिक्षा और कौशल विकास जैसी सेवाओं पर जोर दिया गया है। मार्च 2026 तक देशभर में भिक्षावृत्ति में लगे 31,055 लोगों की पहचान की गई थी, जिनमें 9,855 लोगों का बचाव और पुनर्वास किया गया। इनमें 2,480 बच्चे भी शामिल थे। दिल्ली सरकार के अभियान में भी इसी तरह का समग्र दृष्टिकोण अपनाने की कोशिश है।

इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि किसी बच्चे को सड़क से हटाने के बाद वह दोबारा उसी स्थिति में न लौटे। इसके लिए पुनर्वास के साथ शिक्षा और परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के विकल्प महत्वपूर्ण होंगे।

गर्लफ्रेंड की हत्या का आरोपी भारतीय छात्र जर्मनी में गिरफ्तार, भागने की फिराक में था

एरिजोना में 19 वर्षीय युवती की मौत का मामला; पूछताछ कर रही जांच एजेंसी

एजेंसी। बर्लिन

अमेरिका के एरिजोना में अपनी 19 वर्षीय गर्लफ्रेंड की हत्या के आरोपी भारतीय नागरिक वरुण बाचिगरी को जर्मनी में गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस के अनुसार, यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना की छात्रा जुलिसा रूबी सालाजार टक्सन स्थित अपने अपार्टमेंट में मृत मिली थी। जांच में गला घोटने के संकेत मिलने के बाद उसके 20 वर्षीय भारतीय बॉयफ्रेंड को मुख्य आरोपी बनाया गया।

अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, युवती की मौत के बाद आरोपी अमेरिका से निकल गया और जर्मनी पहुंचा। उस पर आगे भारत जाने की कोशिश करने का भी आरोप है। अमेरिकी जांच एजेंसियों और जर्मन अधिकारियों के समन्वय से उसे जर्मनी पहुंचते ही हिरासत में ले लिया



गया। अब उसे एरिजोना प्रत्यर्पित किए जाने की प्रक्रिया शुरू होगी।

रिशता खत्म करना चाहती थी युवती: जांच से जुड़े अधिकारियों के अनुसार, सालाजार आरोपी के साथ अपना रिश्ता खत्म करना चाहती थी। उसके दोस्तों और परिचितों ने कथित तौर पर उसके व्यवहार को लेकर चिंता जताई थी। पुलिस को युवती के शव पर चोट के निशान मिले हैं और मौत की परिस्थितियों

की जांच जारी है। आरोपी पर प्रथम श्रेणी की हत्या समेत गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरोपी को फिलहाल जर्मनी में रखा गया है। अमेरिकी अधिकारियों की ओर से उसके प्रत्यर्पण की कार्रवाई की जा रही है। मामले में अमेरिकी और जर्मन एजेंसियां आपसी समन्वय से आगे की जांच कर रही हैं। आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप अदालत में साबित होना बाकी हैं।

जंग खत्म करने पर ट्रंप का बदला रुख होर्मुज खोलने पर समझौते के संकेत, परमाणु समझौता अनिवार्य नहीं

एजेंसी। वॉशिंगटन

ईरान के साथ जारी सैन्य संघर्ष को खत्म करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब परमाणु समझौते को अनिवार्य शर्त मानने के बजाय रणनीतिक जलमार्ग होर्मुज को दोबारा खुलवाने पर अधिक जोर दे रहे हैं। ताजा रिपोर्टों के मुताबिक ट्रंप अपने सलाहकारों के साथ इस संभावना पर विचार कर रहे हैं कि यदि ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य को पूरी तरह खोल देता है तो परमाणु समझौता हुए बिना भी युद्ध समाप्त करने का रास्ता निकाला जा सकता है। यह बदलाव लंबे समय से चल रहे संघर्ष और उसके आर्थिक प्रभावों के बीच अमेरिकी रणनीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन माना जा रहा है। होर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में से एक है। इसके आसपास तनाव बढ़ने से तेल आपूर्ति, समुद्री परिवहन और वैश्विक बाजारों पर दबाव बढ़ा है। ईरान ने जलमार्ग को खोलने



के बदले अमेरिका से कई रियायतों की मांग रखी है, जिनमें युद्ध से हुए नुकसान का मुआवजा, प्रतिबंधों में राहत और अमेरिकी सैन्य दबाव में कमी जैसे मुद्दे शामिल हैं। वहीं, रिपब्लिकन पार्टी कांग्रेस के किसी एक या दोनों सदनों में नियंत्रण खो देती है तो ट्रंप की विधायी क्षमता पर अंकुश लग सकता है। हालांकि राष्ट्रपति के कार्यकारी अधिकार पूरी तरह समाप्त नहीं होंगे, लेकिन बजट, कानून और प्रशासनिक नीतियों पर कांग्रेस का विरोध उनकी सरकार के लिए बड़ी बाधा बन सकता है।

फिलिस्तीनी के गठन को स्वीकार नहीं करेंगे: नेतन्याहू- इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गोजा को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति की योजना के साथ मतभेद सार्वजनिक कर दिए हैं। नेतन्याहू ने स्पष्ट किया है कि जब तक वह प्रधानमंत्री हैं, फिलिस्तीनी राज्य के गठन को स्वीकार नहीं करेंगे। हमास के निरस्त्रीकरण तक इजरायली सेना गाजा से पीछे नहीं हटेगी। इससे ट्रंप की ओर से संघर्ष समाप्त करने और गाजा में नई व्यवस्था कायम करने की कोशिशों में अड़चन पैदा हो गई है।

करीब दो साल बाद भारतीय टेस्ट टीम में लौटे सरफराज खान

एजेंसी। मुंबई

भारतीय बल्लेबाज सरफराज खान की करीब दो साल बाद टेस्ट टीम में वापसी हुई है। उन्हें श्रीलंका के खिलाफ आगामी दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए चोटिल साई सुदर्शन के स्थान पर भारतीय टीम में शामिल किया गया है। सुदर्शन दाएं पैर के अंगुठे में स्ट्रेस फ्रैक्चर के कारण पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं।

सरफराज ने आखिरी बार भारत के लिए नवंबर 2024 में टेस्ट खेला था। इसके बाद वह टीम से बाहर रहे। अब उन्हें एक बार फिर राष्ट्रीय टीम में गाना के साथ मतभेद सार्वजनिक कर दिए हैं। नेतन्याहू ने स्पष्ट किया है कि जब तक वह प्रधानमंत्री हैं, फिलिस्तीनी राज्य के गठन को स्वीकार नहीं करेंगे। हमास के निरस्त्रीकरण तक इजरायली सेना गाजा से पीछे नहीं हटेगी। इससे ट्रंप की ओर से संघर्ष समाप्त करने और गाजा में नई व्यवस्था कायम करने की कोशिशों में अड़चन पैदा हो गई है।

दस्तावेजों में गड़बड़ी कर करोड़ों रुपये की फर्म पर कब्जा, फोन और वेबसाइट भी बंद कर हुए फरार

■ मंडी गोबिंदगढ़ का बड़ा स्टील व्यापारी धोखाधड़ी में शामिल
■ जमीन की बिक्री पर रोक के लिए याचिका दायर
■ आरोपितों के पासपोर्ट जब्त व लुकआउट नोटिस की अपील
समर न्यूज | मोहाली

मोहाली की 51 एकड़ जमीन की धोखाधड़ी में मंडी गोबिंदगढ़ का एक बड़ा स्टील व्यापारी भी शामिल है। सेक्टर 65 की जमीन को दस्तावेजों में गड़बड़ी कर हथियाया गया। आरोपित आदर्श गर्ग, परवनी गर्ग और वेद प्रकाश गर्ग अपने फोन और कंपनी की वेबसाइट तक बंद कर दी गई है। शिकायतकर्ता शिव अग्रवाल ने 51 एकड़ जमीन की बिक्री पर रोक के लिए भी कोर्ट में याचिका दायर कर दी है।

आरोपियों ने धोखे से नई फर्म श्री गणपति लैंड डेवलपर बनाकर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवानी शुरू कर दी जबकि बयाना डी एस बिल्डटेक में



हुए थे। पंचकूला के शिव अग्रवाल ने आरोपितों पर 4.27 करोड़ रुपये प्रति एकड़ के सौदे में धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है।

शिव अग्रवाल ने आरोपितों के पासपोर्ट जब्त करने और लुक आउट नोटिस की भी अपील की है। गड़बड़ी में शामिल पंचकूला निवासी आदर्श गर्ग मंडी गोबिंदगढ़ का बाद स्टील कारोबारी है। पुलिस उनकी तलाश कर रही है।

एमओयू की शर्तें पूरी नहीं की: एमअग्रवाल ने आरोप लगाया कि एमओयू की शर्तें पूरी किए बिना डीएस बिल्डटेक में 45 प्रतिशत हिस्सेदारी ट्रांसफर कर ली गई। शिव

अग्रवाल ने अपने बयान में कहा है कि 14 मार्च 2022 को हुए एमओयू के तहत उनकी हिस्सेदारी के बदले 4.27 करोड़ रुपये प्रति एकड़ की दर से भुगतान किया जाना था, लेकिन आरोप है कि तय शर्तों के अनुसार उन्हें भुगतान नहीं किया गया। एमओयू के तहत अलग-अलग चरणों में भुगतान किया जाना था। उनका आरोप है कि आदर्श गर्ग ने न तो एमओयू के समय निर्धारित राशि का भुगतान किया और न ही बाद की शर्तें पूरी कीं। इसके बावजूद साझेदारी डीड का इस्तेमाल कर डीएस बिल्डटेक में उनकी 45 प्रतिशत हिस्सेदारी अपने नाम ट्रांसफर कर ली गई।

एमसी बलजीत कौर ने कहा- फेस-5 की तर्ज पर नए इलाकों में भी विकास को देंगे रफ्तार, सीवरेज और पानी की समस्या प्राथमिकता



■ सफाई कर्मचारियों की कमी, इंटरनेट तारों और कूड़े की समस्या का समाधान करवाने की मांग
सागर पाहवा | मोहाली
समर न्यूज

नगर निगम की एमसी बलजीत कौर ने कहा कि फेस-5 में करवाए गए विकास कार्यों की तर्ज पर अब वार्ड में शामिल नए क्षेत्रों में भी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने का लक्ष्य

रखा गया है। उन्होंने बताया कि इस बार उनके वार्ड में 3बी2, सेक्टर-71 के कुछ हिस्से और इंडस्ट्रियल एरिया भी शामिल हुए हैं। इन क्षेत्रों के लोगों से संपर्क कर समस्याओं की पहचान की जा रही है, ताकि प्राथमिकता के आधार पर समाधान करवाया जा सके। उन्होंने कहा कि वार्ड के सभी हिस्सों में समान रूप से विकास कार्य करवाने और लोगों को बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बलजीत कौर ने बताया कि फेस-5 में करीब एक करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले काजवे प्रोजेक्ट को पूरा करवाया गया। इसके अलावा बैडमिंटन और वॉलीबॉल के लिए सुविधाएं विकसित की गईं और कोच की व्यवस्था भी करवाई गई। पार्कों की सफाई और रखरखाव,



‘लोगों के सहयोग से तैयार होगा विकास का नया मॉडल’
बलजीत कौर ने कहा कि फेस-5 में लोगों के सहयोग से कई काम पूरे करवाए गए हैं। अब 3बी2, सेक्टर-71, इंडस्ट्रियल एरिया और अन्य नए हिस्सों में भी स्थानीय निवासियों से सुझाव लेकर प्राथमिकताएं तय की जाएंगी। सड़क, सीवरेज, पानी, पार्क और खेल सुविधाओं को धारणबद्ध तरीके से बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा।



नए क्षेत्रों में जरूरत के अनुसार होंगे काम
परविंदर कौर ने कहा कि कुंभड़ा एमसी ने कहा कि एस्टिमेंट तैयार होने के बाद जहां जरूरत होगी, वहां नई पानी और सीवरेज पाइपलाइन बिछाने के साथ अन्य जरूरी विकास कार्य भी करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि केवल एक क्षेत्र तक विकास सीमित न रहे, बल्कि पूरे वार्ड को समान सुविधाएं मिलें, इसी दिशा में काम किया जाएगा।

मतदान

सात सीटों पर मतदान स्थगित; पीएमएल-एन 24 सीटों के साथ सबसे आगे

हिंसा के बीच पीओके में टली तीसरे चरण की वोटिंग

एजेंसी। मुजफ्फराबाद

पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (पीओके) में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान सुरक्षा हालात के कारण टाल दिया गया है। चुनाव आयोग ने पूंछ और सुधनौती जिलों की सात सीटों पर मतदान स्थगित करने का फैसला किया है। यह निर्णय क्षेत्र में जारी तनाव, विरोध-प्रदर्शनों और कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए लिया गया। चुनाव आयोग ने इससे पहले भी सुरक्षा कारणों से मतदान कार्यक्रम में बदलाव किया था। तीसरे चरण में कुल 11 सीटों पर मतदान होना था, लेकिन संशोधित कार्यक्रम के तहत अब केवल बाग और हवेली क्षेत्रों में मतदान कराने की तैयारी है। पूंछ और सुधनौती



की सात सीटों पर मतदान बाद में कराया जाएगा। चुनाव आयोग के अनुसार, गृह विभाग की रिपोर्ट और उम्मीदवारों की ओर से जताई गई चिंताओं के बाद कार्यक्रम में बदलाव किया गया। चुनाव प्रक्रिया पहले ही कई बाधाओं से गुजर रही है। इससे पहले भारी बारिश और भूस्खलन के कारण मुजफ्फराबाद की दो सीटों पर मतदान स्थगित करना पड़ा था। बाद में इन सीटों के परिणाम जारी किए

गए, जिनमें एक सीट पीएमएल-एन और एक पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के खते में गई। पीएमएल-एन को बढ़त: अब तक घोषित परिणामों में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) 24 सीटों के साथ सबसे आगे है। पीपीपी ने 10 सीटें जीती हैं। तीसरे चरण में बची सीटों के परिणाम सत्ता गठन की तस्वीर को और स्पष्ट कर सकते हैं।

चुनाव से पहले और मतदान के दौरान विपक्षी दलों की ओर से अनियमितताओं के आरोप भी लगाए गए हैं। पीपीपी ने पहले चरण के बाद चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। हालांकि चुनाव अधिकारियों ने सुरक्षा और प्रशासनिक कारणों को मतदान कार्यक्रम में बदलाव की प्रमुख वजह बताया है। सुरक्षा बनी सबसे बड़ी चुनौती: पूंछ और सुधनौती क्षेत्र में लंबे समय से तनाव बना हुआ है। रावलकोट में विरोध-प्रदर्शनों और धरनों के कारण चुनाव व्यवस्था प्रभावित हुई है। ऐसे माहौल में मतदानकर्मियों और मतदाताओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी। पहले भी सरकारी कर्मचारियों के लिए मतदान प्रक्रिया सुरक्षा कारणों से टालनी पड़ी थी।

सागर पाहवा | मोहाली
समर न्यूज

जेएलपीएल सेक्टर-82 स्थित कार्यालय में एसी की कॉपर पाइप चोरी करने के मामले में गिरफ्तार आरोपी रिजवान खान को अदालत ने नियमित जमानत दे दी है। मामले की सुनवाई करते हुए मोहाली के सत्र न्यायाधीश ने कहा कि आरोपी सात जुलाई 2026 से न्यायिक हिरासत में है और मामले में कथित चोरी का सामान पहले ही बरामद किया जा चुका है। ऐसे में उसे और हिरासत में रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। अदालत में आरोपी की ओर से दलील दी गई कि उसे मामले में झूठा फंसाया गया है। उसके पास से अब कोई और बरामदगी नहीं होनी

है। चालान पेश करने और ट्रायल पूरा होने में भी काफी समय लग सकता है। इसलिए उसे नियमित जमानत पर रिहा किया जाए। वहीं, सरकारी वकील ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी ने अपने सह-आरोपी के साथ मिलकर शिकायतकर्ता के कार्यालय परिसर में चोरी की थी। दोनों को शिकायतकर्ता पक्ष ने कथित तौर पर चोरी करते हुए मौके पर पकड़ लिया था और चोरी की गई एसी की कॉपर पाइपों सहित पुलिस के हवाले किया था। अभियोजन पक्ष ने आशंका जताई कि जमानत मिलने पर आरोपी साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर सकता है या दोबारा इसी तरह की वारदात कर सकता है। मामला शिकायतकर्ता निर्मल सिंह की शिकायत पर दर्ज किया गया था।